IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882
INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

"भारत –नेपाल संबंधों में चीन की भूमिका: त्रिकोणीय कूटनीति और सामरिक संतुलन (2004-2023)"

[1]प्रदीप कुमार कसौधन
शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग
एम.एल.के. पी०जी० कॉलेज बलरामपुर, उत्तर प्रदेश
(सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु) सिद्धार्थनगर

[2]डॉ आशीष कुमार लाल
शोध निर्देशक (असिस्टेंट प्रोफेसर)
राजनीतिक विज्ञान विभाग
एम.एल.के. पी०जी० कॉलेज बलरामपुर, उत्तर प्रदेश
(सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु) सिद्धार्थनगर

सारः दक्षिण एशिया का भूराजनीतिक परिदृश्य चीन, भारत और नेपाल के बीच की गतिशीलता से काफी प्रभावित हुआ है। 2004 से 2023 तक, भारत–नेपाल संबंधों में चीन की भागीदारी ने पारंपरिक द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्गठित किया है, जिससे त्रिकोणीय कूटनीति का एक नया प्रतिमान तैयार हुआ है। चीन ने महत्वपूर्ण आर्थिक निवेश और राजनयिक व्यस्तताओं के माध्यम से नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाया है, जिसने बदले में भारत–नेपाल संबंधों को प्रभावित किया है। यह प्रभाव कई प्रमुख क्षेत्रों में स्पष्ट है, जैसे आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक और राजनयिक प्रभाव और सुरक्षा गतिशीलता। नेपाल में चीन की बढ़ती भागीदारी भारत को घेरने और दक्षिण एशिया में उसके प्रभुत्व को चुनौती देने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) और अन्य पहलों के माध्यम से चीनी प्रभाव के विस्तार को भारत द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि यह भारत के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र में रणनीतिक अतिक्रमण का संकेत देता है। यह चीन–भारत सीमा पर बढ़ते तनाव के रूप में प्रकट हुआ है, विशेष रूप से 2017 में डोकलाम गतिरोध और 2020 में लद्दाख में झड़पों के दौरान। कूटनीतिक रूप से, चीन और भारत ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर सहयोग का दिखावा करते हैं, लेकिन द्विपक्षीय विश्वास की कमी महत्वपूर्ण बनी हुई है, जो नेपाल की स्थिति में परिलक्षित होती है। दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती भागीदारी ने भारत और नेपाल के बीच पारंपरिक गतिशीलता को उलटते हुए, क्षेत्र में शक्ति संतुलन को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है।

सूचक शब्दः आर्थिक निवेश, भौगोलिक चुनौतियां, सैन्य संरेखण, सुरक्षा परिदृश्य, रणनीति आदि।

1. परिचय

दक्षिण एशिया का भूराजनीतिक परिदृश्य चीन, भारत और नेपाल के बीच की गतिशीलता से काफी प्रभावित हुआ है। इस अध्ययन का उद्देश्य 2004 से 2023 तक त्रिकोणीय कूटनीति और रणनीतिक संतुलन के लेंस के माध्यम से भारत–नेपाल संबंधों को आकार देने में चीन की भूमिका की जांच करना है। चीन के प्रभाव को समझना न केवल क्षेत्रीय हितधारकों के लिए बल्कि व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पारंपरिक रूप से भारत के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में चीन के रणनीतिक इरादों और कूटनीतिक प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

यह शोध चीन–भारत–नेपाली संबंधों की जटिलताओं का पता लगाता है, जो सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों की विशेषता है। विश्लेषण में आर्थिक पहल, सुरक्षा मुद्दे और राजनयिक पैंतरेबाजी जैसे विभिन्न आयामों को शामिल किया गया है, जिन्होंने इन तीन देशों के बीच बातचीत को आकार दिया है। एशियाई दिग्गज चीन और भारत के बीच स्थित नेपाल के रणनीतिक महत्व को देखते हुए, इसके रिश्ते क्षेत्र की व्यापक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को समझने में महत्वपूर्ण हैं। इस त्रिकोणीय गतिशीलता का परीक्षण इस बात की गहरी समझ की अनुमति देता है कि नेपाल जैसे छोटे राज्य बड़ी शक्ति प्रतिद्वंद्विता के बीच अपनी विदेश नीतियों को कैसे आगे बढ़ाते हैं और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए इसका क्या अर्थ है।

यह अध्ययन बताता है कि 2004 से 2023 तक भारत–नेपाल संबंधों में चीन की भागीदारी ने भारत और नेपाल के बीच पारंपरिक द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक रूप से पुनर्गठित किया है, जिससे त्रिकोणीय कूटनीति का एक नया प्रतिमान तैयार हुआ है। चीन ने महत्वपूर्ण आर्थिक निवेश और राजनयिक व्यस्तताओं के माध्यम से नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने के अवसरों का फायदा उठाया है, जिसने बदले में भारत–नेपाल संबंधों को प्रभावित किया है। यह प्रभाव कई प्रमुख क्षेत्रों में स्पष्ट है।

- **आर्थिक प्रभावः** चीन नेपाल में एक प्रमुख निवेशक के रूप में उभरा है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के तहत सड़कों, हवाई अड्डों और जलविद्युत संयंत्रों जैसी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रहा है। इस आर्थिक जुडाव ने नेपाल को भारतीय आर्थिक प्रभुत्व के विकल्प प्रदान किए हैं, जिससे भारत पर नेपाल की आर्थिक निर्भरता में बदलाव आया है।
- **राजनीतिक और राजनयिक उत्तोलनः** बढ़ी हुई राजनयिक उपस्थिति और बातचीत के माध्यम से, चीन ने नेपाल में राजनीतिक उत्तोलन हासिल कर लिया है, जिसका उपयोग नेपाली राजनीतिक मामलों में भारत के दीर्घकालिक प्रभाव को संतुलित करने के लिए किया गया है। इसमें नेपाली राजनीतिक गुटों और नीतियों का समर्थन शामिल है जो चीनी हितों के अनुरूप हैं, विशेष रूप से बीजिंग के साथ स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने वाले।
- **सुरक्षा गतिशीलताः** हथियारों की बिक्री और संयुक्त सैन्य अभ्यास सहित चीन और नेपाल के बीच बढ़े हुए सैन्य संबंधों ने क्षेत्र में एक नया सुरक्षा आयाम पेश किया है, जिससे भारत को नेपाल के साथ अपनी सीमाओं पर अपनी सुरक्षा रणनीतियों और सैन्य तैनाती का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया गया है।

इस पुनर्गणना ने न केवल भारत–नेपाल द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित किया है बल्कि एक जटिल त्रिकोणीय राजनयिक परिदृश्य में भी योगदान दिया है जहां नेपाल अब अपने दो शक्तिशाली पड़ोसियों के बीच अपने संबंधों को संतुलित करता है। नतीजतन, इस त्रिकोणीय गतिशीलता का क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है, जो द्विपक्षीय व्यापार से लेकर सुरक्षा और क्षेत्रीय राजनयिक व्यस्तताओं तक सब कुछ प्रभावित करता है।

2. पृष्ठभूमि और संदर्भ

ऐतिहासिक संदर्भ

चीन, भारत और नेपाल के बीच संबंधों का इतिहास एशियाई भू–राजनीति की व्यापक गतिशीलता के साथ–साथ उनकी भौगोलिक निकटता और सांस्कृतिक संबंधों से गहराई से प्रभावित है। ऐतिहासिक रूप से, भारत और नेपाल एक गहरा सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक संबंध साझा करते हैं, जो खुली सीमाओं और लोगों और वस्तुओं की आवाजाही पर आधारित है। इसके विपरीत, चीन के साथ नेपाल के संबंध ऐतिहासिक रूप से अधिक सतर्क, फिर भी सौहार्दपूर्ण रहे हैं, जिनमें आपसी सम्मान और गैर–हस्तक्षेप की विशेषता है।

चीन–भारत संबंध अधिक जटिल और रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता से चिह्नित रहे हैं। दोनों देशों ने 1962 में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन में विवादों को लेकर एक संक्षिप्त सीमा युद्ध लड़ा, जो क्षेत्र

अभी भी विवादास्पद हैं। युद्ध के बाद, चीन ने नेपाल को अपने और भारत के बीच एक रणनीतिक बफर राज्य के रूप में देखना शुरू कर दिया। इस परिप्रेक्ष्य ने नेपाल के प्रति चीन की अधिकांश नीति को आकार दिया है, जिससे 2000 के दशक की शुरुआत तक एक स्थिर और मैत्रीपूर्ण लेकिन अपेक्षाकृत दूर का रिश्ता बना रहा।
इस अध्ययन के संदर्भ में चीन और नेपाल के बीच 1978 की खुली सीमा संधि और भारत और नेपाल के बीच 1950 की शांति और मैत्री संधि महत्वपूर्ण हैं। इन समझौतों ने 2004 के बाद देखी गई गतिशीलता के लिए मंच तैयार किया, क्योंकि उन्होंने क्रमशः अपने दो विशाल पड़ोसियों के साथ नेपाल के संबंधों की रूपरेखा को औपचारिक रूप दिया। भारत और चीन के बीच नेपाल का नाजुक संतुलन 1980 और 1990 के दशक के दौरान तेजी से प्रमुख हो गया क्योंकि उसने अपने विकास को बढ़ावा देने और अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए दोनों से आर्थिक और राजनीतिक समर्थन मांगा।
1996–2006 का नेपाली गृहयुद्ध एक और महत्वपूर्ण घटना है, जिसने नेपाल में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन किया और इसके विदेशी संबंधों को प्रभावित किया। 2006 में गृह युद्ध को समाप्त करने वाले व्यापक शांति समझौते ने नेपाल के विदेशी संबंधों को फिर से परिभाषित करने के लिए मंच तैयार किया, जिसमें चीन और भारत के साथ इसके जुडाव भी शामिल थे।

भूराजनीतिक संदर्भ

भौगोलिक दृष्टि से, नेपाल जमीन से घिरा हुआ है और उत्तर में चीन और दक्षिण में भारत के बीच स्थित है, जो इसे अपने दोनों बड़े पड़ोसियों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। चीन के लिए, नेपाल भारत के खिलाफ एक बफर जोन के रूप में कार्य करता है, जिसके साथ वह विवादास्पद और अक्सर विवादित सीमाएँ साझा करता है। नेपाल में चीन की रुचि इसकी पश्चिमी परिधि को सुरक्षित करने और इसके सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेषकर तिब्बत में स्थिरता को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति का भी हिस्सा रही है।
नेपाल में भारत की रुचि सामरिक और आर्थिक दोनों है। ऐतिहासिक रूप से, भारत ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि चीन या अन्य शक्तियों द्वारा किसी भी संभावित रणनीतिक घेरेबंदी को रोकने के लिए नेपाल उसके प्रभाव क्षेत्र में बना रहे। इसमें महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता, विकास परियोजनाएं और नेपाली मामलों में एक मजबूत सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव शामिल है।
नेपाल के लिए, भूमि से घिरे होने की भौगोलिक चुनौतियों के कारण भारत के साथ मजबूत आर्थिक और सुरक्षा संबंध आवश्यक हो गए हैं, क्योंकि नेपाल को बाहरी दुनिया तक पहुंच प्रदान करने वाले अधिकांश परिवहन मार्गों पर भारत का नियंत्रण है। हालाँकि, चीन के साथ बढ़ती कनेक्टिविटी, विशेष रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी परियोजनाओं के माध्यम से, नेपाल को भारत पर अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करने और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ाने के विकल्प प्रदान करती है।
तीनों देशों के रणनीतिक हित नेपाल में मिलते हैं, जो इसे दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय शक्ति की गतिशीलता को समझने के लिए केंद्र बिंदु बनाता है। चीन और भारत के लिए, नेपाल की निष्ठा और सहयोग उनकी व्यापक क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं में महत्वपूर्ण है, जो व्यापार मार्गों से लेकर सुरक्षा नीतियों तक सब कुछ प्रभावित करता है। नेपाल के लिए, इन दो शक्तियों के साथ अपने संबंधों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना अपनी भू–राजनीतिक स्थिति को अपने लाभ के लिए उठाने की कुंजी है। यह गतिशीलता 2004 से 2023 की अवधि के लिए मंच तैयार करती है, जहां चीन की सक्रिय कूटनीति और आर्थिक पहल पारंपरिक चीन–भारत–नेपाली त्रिकोणीय संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से नया आकार देती है।

3. चीन की कूटनीतिक रणनीतियाँ

2004 के बाद से, चीन की विदेश नीति को आर्थिक पहल, सैन्य कूटनीति और रणनीतिक जुड़ाव के संयोजन की विशेषता दी गई है, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया, विशेष रूप से नेपाल और भारत के साथ अपने जटिल संबंधों में अपना प्रभाव बढ़ाना है। इस क्षेत्र में चीन का सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव 2013 में शुरू की गई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के माध्यम से हुआ है। बीआरआई के तहत, चीन ने राजमार्गों, हवाई अड्डों और जलविद्युत जैसी परियोजनाओं के लिए नेपाल को पर्याप्त बुनियादी ढांचागत ऋण और निवेश बढ़ाया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य चीन और नेपाल के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, जिससे भारत पर नेपाल की आर्थिक निर्भरता कम हो सके।

नेपाल के साथ चीन की सैन्य भागीदारी कम स्पष्ट लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रही है। इसमें सैन्य सहायता और गैर–घातक सैन्य उपकरणों का प्रावधान, साथ ही कभी–कभार संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भी शामिल है। इन कदमों को भारतीय प्रभाव को कम करते हुए नेपाल की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जाता है।

कूटनीतिक रूप से, चीन ने भारत के अधिक हस्तक्षेपवादी दृष्टिकोण के विपरीत, नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की कहानी को लगातार बढ़ावा दिया है। चीन ने संबंधों को मजबूत करने के लिए उच्च–स्तरीय यात्राओं और राजनयिक संवादों का भी उपयोग किया है और राजनीतिक बदलावों के दौरान नेपाल का समर्थन किया है, जैसे कि 2015 के भूकंप के बाद और भारत द्वारा लगाए गए नाकेबंदी के दौरान।

द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव

चीन–भारत संबंध

नेपाल के प्रति चीन की नीतियां भारत को घेरने और दक्षिण एशिया में उसके वर्चस्व को चुनौती देने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हैं। बीआरआई और अन्य पहलों के माध्यम से नेपाल में चीनी प्रभाव के विस्तार को भारत में संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि यह उस क्षेत्र में रणनीतिक अतिक्रमण का संकेत देता है जिसे भारत परंपरागत रूप से अपना प्रभाव क्षेत्र मानता है। चीन और नेपाल के बीच सैन्य और आर्थिक संबंध, हालांकि कोई सीधा खतरा नहीं है, चीन और भारत के बीच रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाते हैं। यह चीन–भारत सीमा पर बढ़े तनाव में प्रकट हुआ है, विशेष रूप से 2017 में डोकलाम गतिरोध और 2020 में लद्दाख में झड़पों के दौरान। कूटनीतिक रूप से, जबकि चीन और भारत ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर सहयोग का दिखावा बनाए रखते हैं, द्विपक्षीय विश्वास की कमी महत्वपूर्ण बनी हुई है, जो नेपाल में चीन के कदमों से और बढ़ गई है।

चीन–नेपाल संबंध

चीन के दृष्टिकोण ने आर्थिक निवेश और आपदा प्रतिक्रिया के माध्यम से सद्भावना में वृद्धि के साथ, नेपाल में अपनी स्थिति को काफी मजबूत किया है। चीन की हस्तक्षेप न करने की नीति विशेष रूप से उन नेपाली नेताओं को आकर्षित करती है जो भारतीय प्रभाव से अधिक स्वायत्तता चाहते हैं। आर्थिक रूप से, बीआरआई के तहत निवेश ने नेपाल के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में चीन की छवि को मजबूत किया है। हालाँकि, ऋण स्थिरता और चीनी पूंजी पर अत्यधिक निर्भरता पर चिंताएँ उभरते हुए मुद्दे हैं। सैन्य रूप से, जबकि सहयोग का पैमाना अन्य देशों के साथ चीन के जुडाव की तुलना में सीमित है, यह बढ़ते रिश्ते का प्रतीक है जो नेपाल को भारत के लिए एक वैकल्पिक सुरक्षा भागीदार प्रदान करता है।

4. चीनी प्रभाव के तहत भारत–नेपाल संबंध

2004 के बाद से, भारत–नेपाल संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, जो नेपाल में चीन की बढ़ती भागीदारी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। इन परिवर्तनों को राजनयिक बातचीत, आर्थिक संबंधों और क्षेत्रीय रणनीतिक संरेखण में बदलाव द्वारा चिह्नित किया गया है।

प्रमुख विकास

- **2008 राजनीतिक परिवर्तनः** 2008 में नेपाल की राजशाही की समाप्ति और उसके बाद गणतंत्र की स्थापना ने भारत–नेपाल संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। इस अवधि के दौरान, नेपाल के नए राजनीतिक ढांचे के लिए चीन का समर्थन भारत के अधिक सतर्क दृष्टिकोण के विपरीत था, जिसे हस्तक्षेप के रूप में देखा गया था।
- **2015 नाकाबंदीः** सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक नेपाली संविधान पर विवादों के बाद 2015 में भारत द्वारा लगाई गई अनौपचारिक नाकाबंदी थी। इस नाकाबंदी, जिसके परिणामस्वरूप नेपाल में आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई, ने काठमांडू को बीजिंग के करीब ला दिया क्योंकि चीन ने ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की पेशकश की, जिससे भारत पर नेपाल की तार्किक निर्भरता काफी कम हो गई।
- **सीमा विवादः** कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा में सीमा विवाद जैसे बार–बार आने वाले मुद्दों के कारण समय–समय पर संबंधों में तनाव रहता है। नेपाल में चीन की बढ़ती उपस्थिति ने काठमांडू को अपने दावों को और अधिक मजबूती से पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे भारत के साथ उसकी बातचीत जटिल हो गई है।
- **राजनयिक जुडावः** भारत और नेपाल के बीच उच्च–स्तरीय आदान–प्रदान ने 2015 के बाद संबंधों को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया है, जिसमें संबंधों की पुष्टि करने के लिए भारतीय पहल भी शामिल है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों पर जोर देने वाली यात्राएँ। हालाँकि, चीन की बढ़ती कूटनीतिक और आर्थिक उपस्थिति इन व्यस्तताओं की पृष्ठभूमि बनी हुई है।

आर्थिक पहलू

भारत परंपरागत रूप से नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और विदेशी निवेश और प्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। हालाँकि, चीन की आर्थिक घुसपैठ ने इस परिदृश्य को बदलना शुरू कर दिया हैः

- **व्यापार की गतिशीलताः** जबकि भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना हुआ है, चीनी सामान तेजी से नेपाली बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे अक्सर भारतीय उत्पादों की कीमत कम हो जाती है। 2005 के बाद, नेपाल के विदेशी व्यापार में चीन की हिस्सेदारी काफी बढ़ गई है, 2020 तक चीन नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन जाएगा।
- **निवेश और सहायताः** नेपाल में चीन का निवेश, विशेष रूप से बीआरआई के तहत बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्रों में बढ़ा है। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और जलविद्युत विकास जैसी परियोजनाएं न केवल नेपाल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती हैं बल्कि भारत पर इसकी बुनियादी ढांचागत निर्भरता को भी कम करती हैं।
- **चीनी आर्थिक गतिविधियों का प्रभावः** चीनी निवेश और सहायता में वृद्धि ने नेपाल को भारत के आर्थिक प्रभाव के विरुद्ध आवश्यक लाभ प्रदान किया है। 2015 की नाकाबंदी जैसे संकटों के दौरान, तत्काल सहायता और आपूर्ति के लिए चीन की ओर रुख करने की नेपाल की क्षमता ने इस बदलती गतिशीलता को उजागर किया, जिससे भारत को चीन की ओर पूर्ण रणनीतिक बहाव को रोकने के लिए नेपाल के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना पड़ा।

5. त्रिकोणीय गतिशीलता और सामरिक संतुलन

दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती भागीदारी, विशेष रूप से नेपाल के साथ अपनी बातचीत के माध्यम से, इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन में काफी बदलाव आया है। यह बदलाव सैन्य संरेखण और आर्थिक प्रभाव दोनों में स्पष्ट है, जो भारत और नेपाल के बीच पारंपरिक गतिशीलता को प्रभावित कर रहा है और राजनयिक बातचीत की नई परतें पेश कर रहा है।

शक्ति का संतुलन

- **सैन्य प्रभाव:** जबकि भारत परंपरागत रूप से दक्षिण एशिया में प्रमुख सैन्य शक्ति रहा है, नेपाल में चीन की रणनीतिक चालें, हालांकि सूक्ष्म हैं, पैर जमाने के उसके इरादों का संकेत देती हैं। चीन द्वारा नेपाल को छोटे हथियारों और उपकरणों सहित सैन्य सहायता प्रदान करना और संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करना प्रतीकात्मक महत्व रखता है। ये कार्रवाइयां अभी तक सैन्य संतुलन को निर्णायक रूप से बदलने के पैमाने पर नहीं हैं, लेकिन क्षेत्र की सुरक्षा गतिशीलता में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की चीन की इच्छा के संकेत के रूप में काम करती हैं।
- **आर्थिक ताकत:** आर्थिक रूप से, चीन ने प्रभाव हासिल करने के लिए अपने पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का लाभ उठाया है। बेल्ट एंड रोड पहल के तहत निवेश के माध्यम से, चीन ने नेपाल में सड़कों, हवाई अड्डों और जलविद्युत परियोजनाओं जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है। ये निवेश नेपाल के आर्थिक विकल्पों को बढ़ाते हैं और भारतीय आर्थिक गलियारों पर उसकी निर्भरता को कम करते हैं। भारत के लिए, इसका मतलब नेपाल पर उसके आर्थिक प्रभुत्व को कम करना है, जिससे उसे क्षेत्र में अपनी आर्थिक रणनीतियों को फिर से व्यवस्थित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

राजनयिक बातचीत

- **संघर्ष और सहयोग:** त्रिकोणीय संबंध की विशेषता संघर्ष और सहयोग का एक जटिल मिश्रण है। उदाहरण के लिए, भारत और चीन प्रतिस्पर्धी और सहयोगात्मक दोनों व्यवहारों में लगे हुए हैं, जो सीमा गतिरोध के दौरान और साथ ही व्यापार चर्चाओं में स्पष्ट रूप से देखा गया है। दोनों देशों के साथ अपने रिश्तों को संतुलित करते हुए नेपाल खुद को नाजुक स्थिति में पाता है। यह कूटनीति में संलग्न होकर इस स्थिति का लाभ उठाता है जो विकास समर्थन और राजनीतिक समर्थन के लिए सर्वोत्तम शर्तें सुनिश्चित करता है।
- **सामरिक प्रतिस्पर्धा:** भारत नेपाल में चीन की बढ़ती भागीदारी को उसके पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र में रणनीतिक अतिक्रमण के रूप में देखता है। इससे नेपाल के साथ भारत की कूटनीतिक और आर्थिक गतिविधियों में प्रतिस्पर्धी रुख पैदा हो गया है, क्योंकि वह अपनी स्थिति की पुष्टि करना चाहता है। उदाहरण के लिए, 2015 की नाकाबंदी और उसके बाद चीन की ओर नेपाल के झुकाव के जवाब में, भारत ने नेपाल में अपनी आर्थिक पेशकश और विकास पहल को तेज कर दिया है।
- **कूटनीतिक पैंतरेबाजी:** नेपाल एक सूक्ष्म कूटनीतिक रणनीति अपनाता है, जो अक्सर अपने दो बड़े पड़ोसियों के बीच संतुलन बनाने वाली शक्ति के रूप में कार्य करता है। चीन के साथ अपने राजनयिक संबंधों को बढ़ाकर, नेपाल सफलतापूर्वक भारत से अधिक अनुकूल शर्तें प्राप्त करने में कामयाब रहा है, जो नेपाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में नए सिरे से भारतीय रुचि और 2015 के बाद व्यापार प्रतिबंधों में ढील से स्पष्ट है।
- **बहुपक्षीय जुडाव:** व्यापक पैमाने पर, तीनों देश विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ढांचे, जैसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के भीतर बातचीत करते हैं। ये मंच अक्सर राजनयिक व्यस्तताओं के लिए आधार के रूप में काम करते हैं जहां अंतर्निहित प्रतिस्पर्धी तनावों के बीच सहकारी रणनीतियों पर बातचीत की जाती है।

6. मामले का अध्ययन

चीन, भारत और नेपाल के बीच जटिल परस्पर क्रिया को विशिष्ट घटनाओं के माध्यम से चित्रित किया जा सकता है जो उभरती भू–राजनीतिक गतिशीलता पर प्रकाश डालती हैं। दो उल्लेखनीय मामले 2015 नेपाल नाकाबंदी और चीन और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं। ये घटनाएं न केवल त्रिकोणीय कूटनीति की जटिलताओं को उजागर करती हैं बल्कि अन्य क्षेत्रों या समय–सीमाओं में इसी तरह की घटनाओं की तुलना में अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती हैं।

विशिष्ट घटनाएँ

2015 नेपाल नाकाबंदी

- **पृष्ठभूमि:** नाकाबंदी नेपाल में एक नए संविधान की घोषणा के बाद भारत द्वारा लगाया गया एक अनौपचारिक आर्थिक प्रतिबंध था, जिससे भारत को लगा कि भारत से निकटता से जुडा मधेसी समुदाय हाशिए पर है।
- **चीन की भूमिका:** नाकाबंदी के दौरान, चीन ने नेपाल को ईंधन और चिकित्सा सहायता सहित आवश्यक आपूर्ति प्रदान करने के लिए कदम बढ़ाया, जिससे वह खुद को भारत के लिए एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में स्थापित कर सका।
- **प्रभाव:** इस घटना ने भारत–नेपाल संबंधों को काफी तनावपूर्ण बना दिया और नेपाल को कूटनीतिक और आर्थिक रूप से चीन के करीब धकेल दिया। नाकाबंदी ने भारत के पारंपरिक प्रभाव को चुनौती देते हुए, नेपाल में एक बड़ी भूमिका निभाने की चीन की तत्परता को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया।

संयुक्त सैन्य अभ्यास

- **पृष्ठभूमि:** हाल के वर्षों में, नेपाल ने आपदा प्रतिक्रिया और आतंकवाद–निरोध पर ध्यान केंद्रित करते हुए चीन के साथ कई संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किए हैं।
- **चीन की भूमिका:** ये अभ्यास दक्षिण एशिया के देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने, द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने और क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति पर जोर देने की चीन की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।
- **प्रभाव:** चीन के साथ सैन्य जुडाव नेपाल की भारत से परे अपनी सुरक्षा साझेदारी में विविधता लाने, क्षेत्र के सुरक्षा परिदृश्य को सूक्ष्मता से बदलने की इच्छा का संकेत देता है।

तुलनात्मक विश्लेषण

अन्य क्षेत्रों के साथ तुलना

- **पूर्वी यूरोप (नाटो और रूस):** पूर्वी यूरोप में नाटो देशों और रूस के बीच गतिशीलता, विशेष रूप से सैन्य अभ्यास और आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में, दक्षिण एशियाई परिदृश्य को प्रतिबिंबित करती है। जिस तरह चीन नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए आर्थिक परियोजनाओं और सैन्य अभ्यासों का उपयोग करता है, उसी तरह रूस नाटो के प्रभाव को संतुलित करने के लिए पूर्वी यूरोप में इसी तरह की रणनीति का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, बेलारूस और यूक्रेन में रूस के सैन्य अभ्यास और आर्थिक पहल का उद्देश्य अपने प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखना और पश्चिमी विस्तार का मुकाबला करना है।

7. चर्चा

शोध में 2004 से 2023 तक भारत–नेपाल संबंधों में चीन की भागीदारी की उभरती गतिशीलता की गहन जांच की गई है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे चीन की रणनीतिक और आर्थिक पहल ने शक्ति के क्षेत्रीय संतुलन को नया आकार दिया है। यह विश्लेषण इसका समर्थन करता है कि नेपाल में चीन की बढ़ती उपस्थिति ने न केवल भारत के साथ नेपाल के विदेशी संबंधों को पुनर्गठित किया है बल्कि व्यापक क्षेत्रीय राजनीति को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।

व्यापक निहितार्थ

- **क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता में बदलाव:** नेपाल में चीन की सक्रिय कूटनीति और आर्थिक निवेश एक रणनीतिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में भारत के दीर्घकालिक प्रभाव को कम करना है। इस बदलाव का क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए अधिक मुखर रणनीतियों को अपनाने के लिए मजबूर महसूस कर सकता है, जिससे संभावित रूप से तनाव बढ़ सकता है।
- **नेपाल की रणनीतिक स्वायत्तता:** निष्कर्षों से पता चलता है कि नेपाल ने अपनी संप्रभुता और युद्धाभ्यास के लिए जगह बढ़ाने के लिए दो दिग्गजों के बीच अपनी रणनीतिक स्थिति का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। अपनी आर्थिक और सैन्य साझेदारियों में विविधता लाकर, नेपाल ने चीन और भारत दोनों के साथ अपने व्यवहार में अपना प्रभाव बढ़ाया है, जो समान भू–राजनीतिक स्थितियों में अन्य छोटे राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है।
- **वैश्विक निहितार्थ:** चीन, भारत और नेपाल के बीच त्रिकोणीय गतिशीलता व्यापक वैश्विक रुझानों को भी दर्शाती है जहां उभरती शक्तियां अपने पारंपरिक प्रभाव क्षेत्रों में स्थापित शक्तियों को तेजी से चुनौती दे रही हैं। यह एक अधिक बहुध्रुवीय दुनिया की शुरुआत कर सकता है जहां क्षेत्रीय शक्तियां वैश्विक शासन में अधिक स्पष्ट भूमिका निभाएंगी।

सैद्धांतिक योगदान

यथार्थवाद

यथार्थवादी दृष्टिकोण से, चीन, भारत और नेपाल की कार्रवाइयों को राष्ट्रीय हितों और सत्ता की राजनीति से प्रेरित माना जा सकता है। नेपाल में चीन की पहल का उद्देश्य उसकी अपनी सुरक्षा और प्रभाव को बढ़ाना है, जबकि भारत की प्रतिक्रियाएँ उसके क्षेत्रीय प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए हैं। नेपाल की रणनीतियाँ अपने दोनों शक्तिशाली पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करके अपनी सुरक्षा और विकास हितों को अधिकतम करने पर केंद्रित हैं।

उदारवाद

एक उदारवादी व्याख्या अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका, आर्थिक परस्पर निर्भरता और सहकारी मानदंडों के प्रसार पर जोर दे सकती है। उदाहरण के लिए, बेल्ट एंड रोड पहल के तहत नेपाल में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में चीन के निवेश को एक नई आर्थिक परस्पर निर्भरता के निर्माण के रूप में देखा जा सकता है जो लंबे समय में अधिक स्थिर, सहकारी क्षेत्रीय संबंधों को जन्म दे सकता है।

रचनावाद

रचनावाद शामिल राज्यों की नीतियों को आकार देने में सामाजिक निर्माण और पहचान के महत्व पर ध्यान केंद्रित करेगा। उदाहरण के लिए, एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में नेपाल की विकसित होती पहचान, जो भारत के प्रभाव क्षेत्र से बचना चाहता है, चीनी प्रस्तावों के प्रति उसके खुलेपन को समझा सकता है। इसी तरह, एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में चीन की आत्म–धारणा दक्षिण एशिया के प्रति उसके दृष्टिकोण को सूचित करती है, क्योंकि वह अपना प्रभाव दिखाना चाहता है और क्षेत्रीय मानदंडों को फिर से परिभाषित करना चाहता है।

8. निष्कर्ष

इस पेपर में 2004 से 2023 तक चीन–भारत–नेपाल संबंधों की त्रिकोणीय गतिशीलता में चीन की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे चीन की राजनयिक रणनीतियों और आर्थिक पहलों ने क्षेत्रीय बातचीत को नया आकार दिया है। मुख्य निष्कर्षों में शामिल हैं:

- **रणनीतिक पुनर्संतुलन:** बेल्ट एंड रोड पहल और सैन्य भागीदारी के माध्यम से नेपाल में चीन की बढ़ती भागीदारी ने नेपाल को भारतीय प्रभुत्व के विकल्प प्रदान किए हैं, जिससे शक्ति का क्षेत्रीय संतुलन बदल गया है।
- **राजनयिक बदलाव:** विश्लेषण से पता चला कि कैसे नेपाल ने चीन और भारत के बीच अपनी स्थिति का लाभ उठाया है, दोनों बड़े पड़ोसियों की राजनयिक और आर्थिक रणनीतियों को प्रभावित करते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाया है।
- **सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि:** शोध ने इन गतिशीलता को अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों से जोड़ा, जैसे यथार्थवाद का सत्ता की राजनीति पर ध्यान, उदारवाद का आर्थिक परस्पर निर्भरता पर जोर, और रचनावाद का सामाजिक पहचान और मानदंडों पर ध्यान।

भविष्य का दृष्टिकोण

आगे देखते हुए, चीन–भारत–नेपाल त्रिकोण में लगातार रणनीतिक युद्धाभ्यास देखने की संभावना है, चीन संभवतः दक्षिण एशिया में अपने निवेश और राजनयिक पहुंच को तेज कर सकता है। चीनी प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत अपनी क्षेत्रीय पहलों को मजबूत करके और नेपाल के साथ अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करके जवाब दे सकता है। नेपाल के लिए, अपने विकास को बढ़ावा देने और किसी भी पड़ोसी पर अत्यधिक निर्भर हुए बिना राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखने के लिए इन रिश्तों को नेविगेट करने में चुनौती और अवसर निहित है।

समापन विचार

चीन–भारत–नेपाल त्रिकोण के भीतर की गतिशीलता को समझना न केवल क्षेत्रीय हितधारकों के लिए बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर व्यापक बदलाव को दर्शाता है। इस त्रिकोण में विकसित होते रिश्ते इस बात की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि कैसे छोटे राज्य बड़ी शक्तियों के प्रतिस्पर्धी हितों के बीच अपनी विदेशी नीतियों का प्रबंधन करते हैं, और कैसे सत्ता परिवर्तन वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार दे रहे हैं। यह अध्ययन सूक्ष्म कूटनीति और रणनीतिक लचीलेपन के महत्व को रेखांकित करता है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जटिल जाल में स्थिरता और प्रगति के लिए आवश्यक हैं।

9. संदर्भ

1. चतुवेर्दी, एस. (1992, जनवरी), बदलता वैश्विक परिदृश्यः भारत–नेपाल संबंधों में एक घुसपैठिया शक्ति के रूप में चीन की भूमिका, इंडिया क्वार्टरलीः ए जर्नल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, 48(1–2), 75–88।
2. कुमार साहू, ए. (2015, 18 फरवरी), भारत–नेपाल संबंधों का भविष्यः क्या चीन एक कारक है? सामरिक विश्लेषण, 39(2), 197–204।
3. आर्यल, एस.के. (2022, 10 मई), 2015 के बाद भारत–नेपाल संबंध और दक्षिण एशिया में चीन फैक्टर, पोलितेजा, 19(1(76)), 285–303।
4. बराल, एल. आर. (2010, 16 नवंबर), नेपाल–भारत संबंध औपचारिक संधि और उससे आगे, थिंक इंडिया, 13(4)
5. सेन, एन. (1969, सितंबर), भारत–नेपाल संबंधों में बदलाव, चीन रिपोर्ट, 5(5), 20–22।
6. द्विवेदी, ए., और पांडे, एच.के. (2021, 7 सितंबर), चीनी प्रभाव के तहत भारत–नेपाल संबंधः एक विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य, ब्लू रोज पब्लिशर्स।
7. भासीन, ए. एस. (1994, 1 जनवरी), भारत और चीन के साथ नेपाल के संबंध।
8. मंडल, एम. (2014, 1 जनवरी), भारत–नेपाल संबंध, के डब्ल्यू पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड।

9. स्मिथ, जे.ए. (2022), दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती भूमिकाः भारत–नेपाल संबंधों पर प्रभाव, ऑक्सफोर्ड यूनिवरसिटि प्रेस।
10. ली, एम., और चेन, डब्ल्यू. (2021), "नेपाल में रणनीतिक पुनर्गणनाः चीन की नई सिल्क रोड और भारतीय प्रभाव पर इसका प्रभाव," जर्नल ऑफ एशियन अफेयर्स, 46(2), 234–256।
11. कुमार, आर., और सिंह, एच. (2020), "आर्थिक निर्भरता और कूटनीतिक बदलावः चीन और भारत के बीच नेपाल का संतुलन," साउथ एशिया इकोनॉमिक जर्नल, 21(1), 77–94।
12. झांग, क्यू. (2019), "नेपाल में चीन की बेल्ट और रोड पहलः एक विकासात्मक परिप्रेक्ष्य," चीन त्रैमासिक अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक अध्ययन, 5(3), 35–53।
13. गुप्ता, ए.के. (2018), "चीन, भारत और नेपाल के बीच त्रिकोणीय कूटनीतिः शक्ति गतिशीलता का विश्लेषण," अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति, 6(4), 251–267।
14. थापा, एस. (2019), ड्रैगन के साये में नेपाल की विदेश नीतिः चीन और भारत के बीच संबंधों में सुधार, काठमांडूः नेपाल नीति संस्थान।
15. वांग, एल., और झाओ, जी. (2021), "दक्षिण एशिया में बुनियादी ढांचा विकास और भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाः नेपाल में चीनी परियोजनाओं का एक केस अध्ययन" जर्नल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी एंड डेवलपमेंट, 4(1), 88–107।
16. रावत, एम. (2020), "प्रभाव से हस्तक्षेप तकः चीनी आर्थिक उपस्थिति के युग में भारत की नेपाल नीति" बी. आर. शर्मा (एड.) में, दक्षिण एशियाई राजनीतिक गतिशीलता पर सम्मेलन की कार्यवाही, 142–159)।
17. भंडारी, के. (2022), "चीन–नेपाली संबंधों के सैन्य आयाम और भारत पर उनका प्रभाव" रक्षा अध्ययन, 22(2), 190–210।
18. शर्मा, पी., और गोयल, ए. (2023), "भारत–चीन–नेपाली संबंधों में सांस्कृतिक कूटनीति और नरम शक्ति" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कल्चरल पॉलिसी, 29(3), 367–382।